जलवायु मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी की घोषणाओं से भारत को बढ़त

लक्ष्य

नई दिल्ली | मदन जैड़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में जलवायु खतरों से निपटने के लिए भारत की महत्वाकांक्षी कार्ययोजना पेश की है। उन्होंने पंचामृत के नाम से जो पांच घोषणाएं की हैं, उससे विश्व में भारत को एक बार फिर जलवायु मोर्चे पर बढ़त हासिल हो गई है। भारत की इस पहल से विकसित देशों पर भी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का दबाव बढ़ेगा।

एक दिन पहले ही जी-20 देशों द्वारा सदी के मध्य तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के ऐलान के बाद दुनिया की नजरें भारत की तरफ थीं, क्योंकि समूह में कुछ ही देश रह गए थे जिन्होंने अभी तक शून्य उत्सर्जन पर पत्ते नहीं खोले थे। बहरहाल 2070 तक भारत को शून्य कार्बन उत्सर्जन राष्ट्र बनाने की मोदी की पहल को बेहद सुलझा हुआ कदम माना जा रहा है। इस प्रकार भारत को कार्य करने के लिए 50 वर्ष का समय भी मिल जाएगा।

2030 तक के लिए चार लक्ष्यः भारत ने सिर्फ दूर का लक्ष्य रखकर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं की है। उसने अपने कम अवधि के लक्ष्यों में भी बढोतरी की है। 2030 तक के लिए 4 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को कुल बिजली की खपत का 50 फीसदी तक करने का लक्ष्य रखा है जबकि मौजूदा कार्यक्रम के तहत इसे 40 फीसदी करना था। इसमें से भारत 2021 में ही 39 फीसदी क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य हासिल कर चुका है। भारत ने पूर्व में 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा था।

500
गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य 450 से बढ़ाकर किया

नेतृत्व प्रदर्शित करने का अवसर : माथुर

इंटरनेशनल सोलर एलायंस के प्रमुख डॉ. अजय माथुर ने कहा कि इन घोषणाओं से भारत को जलवायु मोर्चे पर विश्व को एक बार फिर नेतृत्व प्रदर्शित करने का अवसर मिला है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत के इस कदम का असर विकसित देशों पर भी पड़ेगा और वह जलवायु वित्त पोषण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को पूरी करेंगे।

जलवायु पर निवेश बढ़ाना होगा

डब्ल्यूआरआई की विशेषज्ञ उल्का केलकर ने कहा कि भारत को इन घोषणाओं को साकार करने के लिए जलवायु पर निवेश बढ़ाना होगा।

कॉप-26 के लिए चुनौती

ग्रीनपीस इंटरनेशनल के कार्यकारी निदेशक जेनिफर मार्गन ने कहा कि जी-20 देश कॉप-26 के लिए सफलता की जमीन तैयार करने में विफल रहे हैं। उनका विजन और लक्ष्य बेहद कमजोर हैं। जी-20 देशों में रूस, भारत और अर्जेंटीना को छोड़कर सभी देश पहले ही नेट जीरो का ऐलान कर चुके हैं।

इसमें अब तक अच्छी प्रगति हुई है। इसलिए पीएम ने इसे बढ़ाकर 500 गीगावाट कर दिया है। तीसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता को 45 फीसदी तक कम करने का ऐलान किया है। पेरिस समझौते के तहत भारत ने इसमें 33-35 फीसदी कमी की घोषणा की थी और इस लक्ष्य के बड़े हिस्से को पहले ही हासिल कर चुका है। चौथी घोषणा 2030 तक एक अरब टन कार्बन उत्सर्जन कम करने का है।

भारत की घोषणाएं बेहद अहमः जलवायु मोर्चे पर भारत की इन घोषणाओं को बेहद अहम माना जा रहा है। भारत का अब तक का काम भी अच्छा रहा है। जी 20 देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जो दो डिग्री तापमान बढ़ोतरी की राह पर था। बाकी देश तीन प्रतिशत या इससे भी अधिक बढ़ोतरी की ओर बढ़ रहे थे। नई घोषणाओं के बाद भारत तापमान को डेढ़ डिग्री की बढ़ोतरी तक सीमित रखने की ओर अग्रसर होगा।